From

The Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department

To

1. Chief Secretary to Government Haryana, Chandigarh.
2. The Registrar General , Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.

Memo No.: 2/14/2018-1Pension(FD)
Dated: Chandigarh, the 09th September, 2024

Subject: **Rule for revision of Pension / family pension of Retired Judicial Officers of Government of Haryana.**

Sir,

I am directed to enclose the copies of notification No. 2/14/2018-1Pension(FD) dated **05.08.2024** with regard to the following Rules published in Haryana Government e-Gazette, on 13.08.2024 for information and necessary action:-

1. Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service (Revised Pension) Part I Rules, 2024 in English and Hindi (13 pages).

2. Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service (Revised Pension) Part II Rules, 2024 in English and Hindi (12 pages).

You are requested to bring the above notification to the notice of retired Judicial Officers of Haryana Government.

The above notification can be downloaded from the website of Finance Department **www.finhry.gov.in** and the same is also available on the website of e-gazette i.e. **https://www.egazetteharyana.gov.in/Gazette/Ordinary/2024/33-2024/20143.pdf** & **https://www.egazetteharyana.gov.in/Gazette/Ordinary/2024/33-2024/20142.pdf**

DA/As above

Yours faithfully,

Manjit Kaur

Joint Secretary Finance (Pension)
for Additional Chief Secretary to Government Haryana
Finance Department

9/9/2024

16/9/2024

Endst. No: 2/14/2018-1Pension(FD) Dated: 09th September, 2024

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:

1. Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. Director General, Treasuries & Accounts Department, Haryana. # 30 Bays Building, Sector 17, Chandigarh.
3. In-Charge, Computer Cell, Finance Department for placing the instructions on the website of Finance Department's i.e. **www.finhry.gov.in.**

Manjit Lal

Joint Secretary Finance (Pension)
for Additional Chief Secretary to Government Haryana
Finance Department
9/9/2024

Endst.No. : 2/14/2018-1Pension(FD) Dated: 09th September, 2024

A copy is forwarded to the Secretary, Council of Ministers, Haryana w.r.t. their U.O. No. 9/106/2024-2Cabinet dated 05.08.2024 for information and necessary action.

Manjit Lal

Joint Secretary Finance (Pension)
for Additional Chief Secretary to Government Haryana
Finance Department
9/9/2024

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2024

संख्या 2/14/2018–1पैंशन (एफ डी).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग–1 नियम, 2024 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. (1) ये नियम हरियाणा सरकार के उन सभी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों पर लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 को पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अधीन अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय है। इन नियमों का लागूकरण।

(2) ये नियम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

3. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''विद्यमान सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों'' से अभिप्राय है, पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्त/मुत्यु के फलस्वरूप प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था;

(ख) ''विद्यमान पेंशन'' से अभिप्राय है, 31 दिसम्बर, 2015 को (संराशित पेंशन, यदि कोई हो,) सहित मूल पेंशनः

परंतु 31 दिसंबर, 2015 को सेवानिवृत्त होने वाले और प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होने वाले न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में, उनकी पेंशन पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के उपबन्धों के अधीन नियत की जाएगी और उसके उपरांत इन नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी;

(ग) ''विद्यमान पारिवारिक पेंशन'' से अभिप्राय है, पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अधीन 31 दिसंबर, 2015 को प्राप्त की जा रही मूल पारिवारिक पेंशनः

परंतु प्रथम जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होने वाले पारिवारिक पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन, इन नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, इन नियमों द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा से उपबंधित के सिवाए, वित्त विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकित

4. (1) वर्ष 2016 से पूर्व हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की हकदारी निम्नलिखित अनुसार निर्धारित की जाएगीः–

(क) 31 दिसम्बर, 2015 तक विद्यमान मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.81 के गुणक से गुणा करके। इस प्रकार प्राप्त पुनीरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को अगले उच्चतर रुपए में पुर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणः– श्रीमान पेंशनभोगी 'एक्स' (जिला न्यायाधीश) 57700–70290/– रूपए के वेतनमान में 31.12.2015 को 67210/– रूपए अंतिम वेतन प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त अधिकारी 67210/– रूपए पर 50 प्रतिशत की दर से 33605/–रूपए पेंशन प्राप्त कर रहा है।

तालिका

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रुपयों में)
1.	31 दिसम्बर, 2015 को मूल पेंशन	33,605.00
2.	इन नियमों के अधीन पुनरीक्षित पेंशन (2.81 से गुणा करते हुए) (₹33,605 x 2.81) = ₹94,430/–	94,430.00

अथवा

(ख) उस वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स, जिसमें वे सेवानिवृत्त हुए थे/उनकी मुत्यु हुई थी (वेतनमान के पुनरीक्षण हेतु सूत्र पर आधारित प्रत्येक मध्यवर्ती न्यायिक वेतन आयोग के अधीन), के समरूप वेतनमान में उनका वेतन अप्रयोगमूलक रूप में पुनरीक्षित करके। तद्नुसार, प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 की निर्धारित तालिका के अनुसार संगणित की जाएगी।

पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपरोक्त खण्ड (क) या (ख), जो भी अधिक हो, में यथा वार्णित सूत्र के अनुसार संगणित की जाएगी।

(2) इस प्रयोजन हेतु, विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन, 75 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले पुराने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन के अंश के बिना केवल मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी। पुराने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भुगतान योग्य अतिरिक्त पेंशन/परिवारिक पेंशन इन नियमों के नियम 7 के अनुसार संगणित की जाएगी।

(3) प्रथम जनवरी, 2016 से प्रतिमास न्यूनतम पेंशन 38,920/– रूपये और प्रतिमास न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 23,350/– रूपये होगी (पुराने पेंशनभोगियों को प्रदत्त अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन को छोड़कर)। हरियाणा सरकार में अधिकतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन, उच्चतर वेतन प्रतिमास 2,24,100/– रूपये का 50 प्रतिशत अर्थात् 1,12,050/– रूपये प्रतिमास और 30 प्रतिशत अर्थात् 67,230/– रूपये प्रतिमास होगी।

अनुपातिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

5. इन नियमों के अधीन पेंशन की हकदारी, इन नियमों के नियम 4 के अनुसार संगणित की जाएगी और आगे सभी मामलों में, जहाँ पेंशनभोगी की सेवा पूर्ण पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा से कम है, तो पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] में यथा विहित अनुपात में कम की जाएगी। आवश्यक न्यूनतम सेवा, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मुत्यु के समय लागू नियमों के उपबंधों के अधीन सुविचारित की जाएगी।

पेंशन के संराशित भाग की कटौती।

6. चूंकि समेकित पेंशन की हकदारी में पेंशन का संराशित भाग भी शामिल होगा, संराशित भाग, जहाँ भी लागू हो, की कटौती मासिक वितरण करते समय पेंशन की उक्त राशि से की जाएगी।

7. (1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा, नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात्:– अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

तालिका

क्रम संख्या	पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा निम्नलिखित आयु प्राप्त करने पर	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
1	2	3
1.	75 वर्ष किन्तु 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
2.	80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
3.	85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
4.	90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60 प्रतिशत
5.	95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80 प्रतिशत
6.	100 वर्ष या से अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(2) पेंशन संवितरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्म तिथि तथा आयु, पेन–I {प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा द्वारा जारी} तथा पेंशन भुगतान आदेश में निरपवाद रूप से दर्शाई गई है ताकि उन द्वारा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ज्योंहि देय होती है, के भुगतान को सुकर बनाया जा सके। यदि आवश्यक सूचना पेन–I {प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा द्वारा जारी} में उपलब्ध नहीं है, तो उन मामलों में, अतिरिक्त पेंशन को विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन में जोड़ने से पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) हरियाणा से आवश्यक सूचना प्राप्त की जाएगी। अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाएगा।

उदाहरणः यदि जहाँ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 75 वर्ष से अधिक आयु का है तथा उसकी समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, इन नियमों के नियम 4 के अनुसार 10,000/– रूपये प्रतिमास है, तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन, (i) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन = 10,000/– और (ii) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन = 2000/– रूपये प्रतिमास अनुसार दर्शाई जाएगी।

(3) 75 वर्ष तथा उससे अधिक आयु पूरी करने पर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि, उस मास के प्रथम दिन से अनुज्ञेय होगी, जिसमें उसके जन्म की तिथि पड़ती है।

उदाहरणः यदि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 12 मई, 2023 को 75 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह प्रथम मई, 2023 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होगा।

(4) विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर महँगाई राहत भी, समय–समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

8. उपरोक्त नियम 4 के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्रथम जनवरी, 2016 से ''मूल पेंशन'' या ''मूल पारिवारिक पेंशन'' जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा। उसके बाद, प्रथम जनवरी, 2016 से मंहगाई राहत सहित प्राप्त की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत महँगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्हक होगी। महँगाई राहत की हकदारी।

9. (1) इन नियमों के नियम 4 (1) (क) (विद्यमान मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.81 के गुणक से गुणा करके)। पेंशन संवितरण प्राधिकारियों का प्राधिकार।

हरियाणा सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण करने वाले सभी पेंशन संवितरण प्रधिकारियों को, इसके द्वारा, प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा/कार्यालय अध्यक्ष इत्यादि के किसी अन्य प्राधिकार के बिना इन नियम 4 (1) (क) के उपबंधों के अनुसार समेकित दरों पर हरियाणा सरकार के विद्यमान सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र परिवारिक सदस्यों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। तथापि, पेंशन के वितरण से पूर्व पेंशन संवितरण प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि नियतन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सही रूप से किया गया है।

(2) इन नियमों के नियम 4 (1) (ख).—

(उस वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स, जिस पर वे सेवानिवृत्त हुए थे/उनकी मृत्यु हुई थी, के समरूप वेतनमान में उनका वेतन अप्रयोगमूलक रूप में नियत करके), इन नियम 4 (1) (ख) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्रथम जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित करने का उत्तरदायित्व उस विभाग के विभागाध्यक्ष का होगा, जहाँ से न्यायिक अधिकारी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या अपनी मृत्यु से पूर्व अन्त में कार्यरत था और पुनरीक्षित पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करेगा। पेंशन स्वीकृति करने वाला प्राधिकारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को अप्रयोगमूलक आधार पर वेतन के निर्धारण के लिए आग्रह करेगा और यथा शीघ्रता से पुनरीक्षित प्राधिकार जारी करेगा। पुनरीक्षित प्राधिकार, विद्यमान पेंशन भुगतान आदेश संख्या के अधीन जारी किया जाएगा और उसी माध्यम से पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिस माध्यम से मूल पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया था।

(3) जहाँ कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समेकन इन नियमों के अनुसार अलग से किया जा सकता है।

(4) जहाँ किसी पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु, पेंशन भुगतान आदेश पर उपलब्ध है, तो उपरोक्त नियम 7 के अनुसार पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) हरियाणा/कार्यालय अध्यक्ष इत्यादि के प्राधिकार के बिना तुरन्त किया जा सकता है।

(5) पुनरीक्षित समेकित पेंशन के संबंध में उपयुक्त इन्द्राज, पेंशन भुगतान आदेश में दो हिस्सों में पेंशन संवितरण प्राधिकरियों द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(6) पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित पेंशन वितरण के संबंध में सूचना, प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) हरियाणा और हरियाणा के संबंधित खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को भेजी जा सकती है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का भुगतान ।

10. वर्ष 2016 से पूर्व हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र परिवारिक सदस्यों को वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 2/14/2018-1Pension(FD), दिनांक 02 जनवरी, 2019 के अनुसार मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 30 प्रतिशत की दर पर पहले ही भुगतान की जा चुकी अंतरिम राहत के समायोजन के बाद, पेंशन संवितरण प्राधिकारी प्रथम जनवरी, 2016 से भुगतानयोग्य पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की गणना करेगा और बकाया राशि का तुरंत भुगतान करेगा।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनबद्धता।

11. (1) यह सम्भाव्य है कि कुछ मामलों में देय बकायों का अधिक भुगतान गलती से संगणित किया जा सकता है, जो बाद में वसूल किया जाना है। इसलिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी बकायों का आहरण करते समय हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को स्पष्ट करेंगे कि यदि बाद में कोई विसंगति ध्यान में आती है, तो भुगतान, उन राशियों से समायोजन के अध्यधीन किया जा रहा है, जो उनको देय होगी। इस प्रयोजन के लिए, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के समय पर हरियाणा सरकार के प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों से लिखित में इस आशय की वचनबद्धता भी प्राप्त की जाएगी कि अधिक भुगतान, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत समेकन के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है, तो उस द्वारा सरकार को या तो भविष्य में भुगतान के समायोजन द्वारा या अन्यथा से उक्त राशि वापस की जाएगी। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नियतन तथा बकायों का समायोजन भी उन कतिपय मामलों में परिशोधन तथा समायोजन के अध्यधीन होगा, जहाँ विशेष पेंशन या अनन्तिम पेंशन विधि न्यायालय के कुछ अंतरिम आदेशों के सामर्थ्य में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को प्रदान की गई थी, मामले के अंतिम रुप से निर्णित होने के बाद, विधि न्यायालय की टिप्पणी/निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए पेंशन संवितरण प्राधिकारी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का वितरण करते समय हरियाणा सरकार के ऐसे सभी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को यह भी स्पष्ट करेंगे कि विधि न्यायालय के ऐसे अन्तिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए समुचित निर्णय के अध्यधीन भुगतान किए जा रहे हैं। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।

अध्यारोही प्रभाव।

12. इन नियमों या इन नियमों की निरन्तरता में जारी किए गए किन्हीं अन्य पश्चात्वर्ती अनुदेशों में यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा सिविल सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या जारी किए गए अनुदेशों के उपबन्ध, ऐसे मामलों, जहाँ पेंशन/पारिवारिक पेंशन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक वे इन नियमों के उपबन्धों से असंगत हों।

13. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो अन्तिम निर्णय के लिए इसे वित्त विभाग में हरियाणा सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। निर्वचन।

14. किसी सामान्य या विशेष परिस्थितियों के मामले में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं या जिनके बारे में कतिपय असंगति ध्यान में आई हों, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुपालित की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी। आगे, यदि सरकार की संतुश्टि हो जाती है कि कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकती है और सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी। अवशिष्ट उपबन्ध।

15. जहाँ सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन में किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो यह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन इन नियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकती या में ढील दे सकती है, जो यह मामले को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति में निपटाने के लिए आवश्यक समझे। ढील देने की शक्ति।

16. पेंशन संवितरण प्राधिकारियों/खजाना अधिकारियों/सहायक खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए इन नियमों को अपने सूचनापट्ट पर तत्काल प्रदर्शित करें। प्रदर्शन।

अनुलग्नक क

[देखिए नियम 11(1)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि यदि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत नियतन के परिणामस्वरुप अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है या बाद में ध्यान में आई विसंगतियों के दृष्टिगत कोई अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है, तो मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान : हस्ताक्षर...

नाम...

पता...

अनुलग्नक ख

[देखिए नियम 11(2)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि किसी विधि न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के आधार पर मुझे दी गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन में किसी परिशोधन या समायोजन के परिणामस्वरूप, विधि न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए सुसंगत समूचित निर्णय के परिणामस्वरूप किसी अधिक राशि का भुगतान किया गया पाया जाता है, तो वह मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा। मैं, आगे ऐसे विधि न्यायालय के यथास्थिति अंतिम निर्णय पर लिए गए सरकार के ऐसे सुसंगत समुचित निर्णय का पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर..

नाम...

पता...

अनुराग रस्तोगी,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 5th August, 2024

No. 2/14/2018-1Pension(FD).—In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service (Revised Pension) Part - I Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

Applicability of these rules.

2. (1) These rules shall apply to all retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members who were drawing their pension/family pension on the 1st January, 2016 under the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016), whose pension/family pension is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

(2) These rules shall not apply to retired Judges of the Punjab and Haryana High Court.

Definitions.

3. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "existing retired Judicial Officer or their eligible family members" means a pensioner/ family pensioner who was drawing pension/family pension prior to the 1st January, 2016 consequent upon his retirement/death.

(b) "existing pension" means the basic pension (inclusive of commuted portion, if any,) as on the 31st December, 2015 :

Provided that in respect of a Judicial Officer retiring on the 31st December, 2015, and becoming entitled to receive pension with effect from the 1st January, 2016, his pension shall be fixed under the provisions of the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016) and thereafter revised as per provisions contained in these rules;

(c) "existing family pension" means the basic family pension to be drawn as on the 31st December, 2015, under the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, as the case may be :

Provided that family pensioners, who become entitled to family pension with effect from the 1st January, 2016, his family pension shall be revised as per provisions contained in these rules;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Finance Department, save as other-wise provided by or under these rules.

Consolidation of pension/family pension.

4. (1) The entitlement of pension/family pension of existing pre-2016 retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members shall be determined as under,-

(a) by multiplying the existing basic pension / family pension (as on the 31st December, 2015) by factor of 2.81. The amount of revised pension /family pension so arrived at shall be rounded off to next higher rupee.

Illustration:- Mr. '**X**' Pensioner (District Judge) retired on the 31st December, 2015 at last pay drawn of Rs. 67,210/- in the pay scale of Rs. 57700-70290. The retired officer is drawing pension @ 50% of Rs. 67210/- i.e. Rs. 33605/-.

Table

Serial Number	Particulars	Amount in Rs.
1.	Basic Pension as on 31st December, 2015	33,605.00
2.	Revised Pension fixed under these rules (using a multiple of 2.81) (Rs. 33605 x 2.81) = Rs. 94,430/-	94,430.00

Or

(b) by notionally fixing their pay corresponding to the pay in the pay scale/pay matrix at which they retired/died (under each intervening Judicial Pay Commission based on the formula for revision of pay). Accordingly, the pension/family pension with effect from the 1st January, 2016 shall be worked out as per the fitment table of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service Revised Pay Rules, 2023.

The revised pension/family pension shall be worked out as per formula as mentioned in clause (a) or (b) above, whichever is higher.

(2) For this purpose, the existing pension/family pension shall be the basic pension/family pension only without the element of additional pension available to the old pensioners/family pensioners attaining the age of 75 years and above. The additional pension/ family pension payable to the old pensioners / family pensioners shall be worked out in accordance with rule 7.

(3) The minimum pension shall be Rs. 38,920/- per month and minimum family pension shall be Rs. 23,350/- per month with effect from the 1st January, 2016 (excluding the additional pension/family pension to the old pensioners). The maximum pension shall be Rs.1,12,050/- per month i.e. 50% and family pension Rs. 67,230/- per month i.e. 30% of the highest pay of Rs.2,24,100/- per month in the Government of Haryana.

Prorata of pension/ family pension.

5. The entitlement of pension under these rules shall be worked in terms of rule 4 of these rules and shall further be reduced pro-rata as prescribed in the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016) in all cases where the pensioner had less than the minimum service required for full pension. The requirement of minimum service shall be considered under the provisions of rules applicable at the time of retirement / death of the employee.

Deduction of commuted portion of pension.

6. As the entitlement of consolidated pension shall be inclusive of commuted portion of pension, the commuted portion, wherever applicable, shall be deducted from the said amount of pension while making monthly disbursements.

Additional Pension/Family Pension.

7. (1) The quantum of additional pension/family pension available to the retired Judicial Officers and their eligible family members, shall continue to be as specified in the table given below, namely:-

Table

Serial number	Attaining age of pensioner / family pensioner	Additional quantum of pension / family pension
1	2	3
1	From 75 years to less than 80 years	20% of revised basic pension / family pension
2	From 80 years to less than 85 years	30% of revised basic pension / family pension
3	From 85 years to less than 90 years	40% of revised basic pension / family pension
4	From 90 years to less than 95 years	60% of revised basic pension / family pension
5	From 95 years to less than 100 years	80% of revised basic pension / family pension
6	100 years or more	100 % of revised basic pension / family pension

(2) The Pension Disbursing Authorities shall ensure that the date of birth and the age of the pensioners/family pensioners is invariably indicated in PEN-I (issued by Principal Accountant General (Accounts & Entitlement), Haryana) and the Pension Payment Order (PPO) to facilitate payment of additional pension / family pension by them as soon as it becomes due. If the requisite information is not available in the PEN-1 [issued by Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana] in those cases, the requisite information may be obtained from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana before adding the additional pension / family pension in the existing basic pension / family pension. The amount of additional pension/ family pension shall be shown distinctly in the pension/family pension payment order.

Illustration: In case where a pensioner /family pensioner is more than 75 years of age and his consolidated pension / family pension in terms of rule 4 of these rules is, Rs. 10,000/- per month, the pension / family pension shall be shown as (i) basic pension/family pension = Rs. 10,000/- and (ii) additional pension/family pension = Rs. 2,000/- per month.

(3) The additional quantum of pension/family pension on attaining the age of 75 years and above shall be admissible from the first day of the month in which his date of birth falls.

Illustration: If a pensioner/family pensioner shall complete age of 75 years on the 12th May, 2023, he shall become entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st May, 2023.

(4) Dearness relief shall also be admissible on the additional quantum of pension / family pension available in accordance with the orders issued from time to time.

Entitlement of dearness relief.

8. The consolidated pension/family pension as worked out in accordance with the provisions of rule 4 above shall be treated as "Basic Pension" or "Basic Family Pension", as the case may be, with effect from the 1st January, 2016. The revised pension/family pension arrived includes dearness relief from the 1st January, 2016 and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter by the Competent Authority from time to time.

Authorization to the Pension Disbursing Authorities.

9. (1) Rule 4 (1) (a) of these rules (Multiplying the existing basic pension/family pension by factor of 2.81).

All Pension Disbursing Authorities handling disbursement of pension to the Haryana Government pensioners/family pensioners are hereby authorized to pay pension/family pension to the existing retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members at the consolidated rates in terms of rule 4 (1) (a) of these rules without any further authorization from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana/ Head of Office etc. However, before disbursement of the pension, the Pension Disbursing Authority shall authenticate that the fixation made is strictly in accordance with the provision of these rules.

(2) Rule 4(1) (b) of these rules.

(By notionally fixing their pay corresponding to the pay in the pay scale/pay matrix at which they retired/died). It shall be the responsibility of the Head of the Department attached to that office from where the Judicial Officer had retired or was working last before his death to revise the pension/family pension of pre the 1st January, 2016 retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members, with effect from the 1st January, 2016 in accordance with rule 4 (1) (b) of these rules and to issue a revised pension payment authority. The Pension Sanctioning Authority shall impress upon the concerned Head of Office for fixation of pay on notional basis and issue revised authority at the earliest. The revised authority shall be issued under the existing pension payment order number and shall travel to the Pension Disbursing Authority through the same channel through which the original pension payment order had travelled.

(3) Where a pensioner is in receipt of more than one pension, consolidation may be done separately in terms of these rules.

(4) Wherever the age of pensioners / family pensioners is available on the Pension Payment Order, the additional pension/family pension in terms of rule 7 above may also be paid by the Pension Disbursing Authority immediately without any further authorization from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana/Head of Office etc.

(5) A suitable entry regarding the revised consolidated pension shall be recorded by the Pension Disbursing Authority in both halves of the Pension Payment Order.

(6) An intimation regarding disbursement of revised pension may be sent by the Pension Disbursing Authority to the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana and concerned Treasury Officer /Assistant Treasury Officer of the Haryana.

10. The Pension Disbursing Authority shall calculate the arrears of revised pension/family pension payable with effect from the 1st January, 2016 after adjustment of interim relief already paid @ 30% of the basic pension/family pension to the pre-2016 retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members, *vide* Finance Department UO No. 2/14/2018-1Pension (FD) dated the 2nd January, 2019 and the balance amount shall be paid immediately. Payment of arrears of pension/family pension.

11. (1) It is not unlikely that the arrears due in some cases may be calculated incorrectly leading to over payment that might have to be recovered subsequently. The Pension Disbursing Authority shall, therefore, make it clear to the retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members while drawing arrears that the payments are being made subject to adjustments from amounts that may be due to them if any discrepancy is noticed later. For this purpose, an undertaking shall also be obtained in writing from every retired Judicial Officer of the Haryana Government and his eligible family members at the time of revision of pension / family pension to the effect that excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect consolidation of pension / family pension, the said amount shall be refunded by him to the Government either by adjustment against future payment or otherwise. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure A. Undertaking for recovery of over payment of pension/ family pension.

(2) The fixation of pension/family pension and adjustment of arrears shall also be subject to rectification and adjustments in certain cases where a particular pension or provisional pension had been granted to a retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members, at the strength of some interim orders of the court of law, after the final disposal of the case suitable appropriate decision may be taken by the Government keeping in view the observations/instructions of the court of law. The Pension Disbursing Authority shall, therefore, also make it clear to all such retired Judicial Officers of the Haryana Government and their eligible family members, while disbursing the arrears of pension/family pension that payments are being made subject to appropriate decision taken by the Government on such final decision of the court of law. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure B.

12. The provisions of the Haryana Civil Services Rules or the Punjab Financial Rules or any other rules or instructions made or issued in this regard shall not save as otherwise provided in these rules or any other subsequent instructions issued in continuation to these rules, apply to cases where pension/family pension is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with the provisions of these rules. Overriding effect.

13. If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government of Haryana in Finance Department for final decision. Interpretation.

14. In the event of any general or special circumstances which are not covered under these rules or about which certain inconsistency are noticed, the matter shall be referred to the Government and the Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions, the Government may, prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government which shall be deemed to be the part of these rules. Residuary provisions.

15. Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Power to relax.

16. The Pension Disbursing Authorities/Treasury Officers/Assistant Treasury Officers are directed to promptly display these rules on their notice board for the benefit of retired Judicial Officers and their eligible family members. Display.

ANNEXURE A

[see rule 11 (1)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that in case excess payment is found to have been made as a result of incorrect fixation of pension/family pension or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature ——————————

Date: Name ——————————

Place: Address ——————————

ANNEXURE B

[see rule 11 (2)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that as a result of any rectification or adjustment in the pension granted to me on the basis of any interim order by any Court of law, any excess amount which is found to have been made as a result of relevant appropriate decision taken by the Government on the final decision of the Court of law, shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise. I further undertake to abide by such relevant appropriate decision of the Government taken on the final decision of such Court of law as the case may be.

Signature——————————

Date: Name ——————————

Place: Address——————————

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

11222—C.S.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2024

संख्या 2/14/2018–1पैंशन (एफ डी).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग–II नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

इन नियमों का लागूकरण।

2. (1) ये हरियाणा सरकार के उन सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं/उनकी मृत्यु हो गई है और जो पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय है।

(2) ये नियम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

प्रभाव की तिथि।

3. इन नियमों के अनुसार पुनरीक्षित उपबंध, उन न्यायिक अधिकारियों को लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है:

परन्तु जहाँ पेंशन/पारिवारिक पेंशन या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन का सरांशीकरण, प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद आने वाले मामले में पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उसे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ पेंशन पूर्व–पुनरीक्षित परिलाभों पर अंतिम रुप से स्वीकृत की जा चुकी है और यदि यह इन नियमों के अधीन हकदारी पेंशन से अधिक लाभकारी है, तो पहले से स्वीकृत पेंशन, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 78 के परंतुक को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगियों के अलाभ के लिए पुनरीक्षित नहीं की जाएगी।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए परिलाभ।

4. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान से अन्यथा विभिन्न पेंशनरी लाभों को संगणित करने के प्रयोजनों के लिए ''परिलाभों'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 9 के उप–नियम (7) के खण्ड (ख) में यथा विहित है।

5. पुनरीक्षित वेतन ढांचा में वेतन से अभिप्राय है, प्रथम जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में प्राप्त किया गया वेतन किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है मूल वेतन।

6. सेवानिवृत्ति/मुत्यु की तिथि को अनुज्ञेय सभी प्रकार के उपदान, मंहगाई भत्ते, इन नियमों के नियम 4 के अनुसार यथा परिभाषित परिलाभों सहित परिलाभों के रुप में समझे जाएंगे। मुत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ।

7. दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पूर्व पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला न्यायिक अधिकारी, पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा, किन्तु वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 32 तथा 35 के अनुसार सेवा उपदान के लिए हकदार समझा जाएगा। पेंशन।

8. (1) कोई न्यायिक अधिकारी, जो बीस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के उपबंधों के अधीन पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। पेंशन की संगणना हेतु उपबंध।

(2) सभी ऐसे मामलों में, जहाँ कोई न्यायिक अधिकारी, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के अनुसार दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अधिवर्षिता पर पेंशन का हकदार हो गया है, तो उसकी पेंशन, उसे अनुज्ञेय पूर्ण पेंशन की राशि के अनुपातिक आधार पर संगणित की जाएगी।

9. (1) हरियाणा सरकार में प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि, क्रमशः प्रतिमास पेंशन 38,920/– रुपए और पारिवारिक पेंशन 23,350/– रुपए और उच्चतर वेतन प्रतिमास 2,24,100/– रुपए का पचास प्रतिशत अर्थात् अधिकतम पेंशन प्रतिमास 1,12,050/– रूपए और तीस प्रतिशत अर्थात् अधिकतम पारिवारिक पेंशन प्रतिमास 67,230/– रुपए के अध्यधीन होगी। पेंशन और पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा।

(2) उप–नियम (1) के उपबंध, उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ किसी न्यायिक अधिकारी का सेवाकाल उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर बीस वर्ष से कम है। इन न्यायिक अधिकारियों की पेंशन, उनके सेवाकाल के दृष्टिगत हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में विहित उपबंधो के अनुसार आनुपातिक रुप से संगणित की जाएगी।

10. (1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में यथा वर्णित के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात्:– अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

तालिका

क्रम संख्या	पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा निम्नलिखित आयु प्राप्त करने पर	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
1	2	3
1.	75 वर्ष किन्तु 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
2.	80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
3.	85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
4.	90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60 प्रतिशत
5.	95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80 प्रतिशत
6.	100 वर्ष या से अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(2) प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्म तिथि और आयु पेन–I तथा पेंशन भुगतान आदेश में निरपवाद रूप से दर्शाई गई है ताकि पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ज्योंहि देय होती है, के भुगतान को सुकर बनाया जा सके। यदि आवश्यक सूचना, पेन–1 {प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा द्वारा जारी} में उपलब्ध नहीं है, तो उन मामलों में, अतिरिक्त पेंशन को विद्यमान मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में जोड़ने से पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा से आवश्यक सूचना प्राप्त की जाएगी। अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रुप से दिखाया जाएगा।

उदाहरणः यदि जहाँ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 75 वर्ष से अधिक आयु का है तथा उसकी समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन इन नियमों के नियम 8 के अनुसार 10,000/– रूपए प्रतिमास है, तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन (i) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन 10,000/–रूपए तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन = 2000/– रूपए प्रतिमास अनुसार दर्शाई जाएगी।

(3) 75 वर्ष तथा से अधिक की आयु पूरी करने पर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि, मास के प्रथम दिन से अनुज्ञेय होगी, जिसमें उसके जन्म की तिथि पड़ती है।

उदाहरणः– यदि कोई पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी मई, 2023 में किसी भी तिथि को 75 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह प्रथम मई, 2023 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी, समय–समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान।

11. (1) मृत्यु–एवं–सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख (बीस लाख) रूपए होगी। जब भी मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मूल वेतन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक हो जाती है, तो उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जाएगी।

(2) मृत्यु उपदान की दर, नीचे दी गई तालिका में यथा वर्णित अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी, अर्थात्:–

तालिका

क्रम संख्या	मृत्यु की अर्हक सेवाकाल की अवधि	मृत्यु उपदान की दर
1	2	3
1	1 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का दो गुणा
2	एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 6 गुणा
3	5 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 12 गुणा
4	11 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 20 गुणा
5	20 वर्ष या उससे अधिक	मासिक परिलाभों का अधिकतम 33 गुणा के अध्यधीन अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मास की अवधि के लिए अर्ध मास के परिलाभ।

पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1964।

12. (1) पारिवारिक पेंशन, पुनरीक्षित वेतन ढांचे में मूल वेतन के 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) की एकरूप दर पर संगणित की जाएगी तथा हरियाणा सरकार में प्रथम जनवरी, 2016 से न्यूनतम 23,350/– रूपए प्रतिमास तथा अधिकतम 67,230/–रूपए प्रतिमास अर्थात् उच्चतर वेतन 2,24,100/– रूपए का 30 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(2) वर्धित पारिवारिक पेंशन की राशि, हरियाणा सरकार में पुनरीक्षित वेतन ढांचे में मूल वेतन का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) होगी और न्यूनतम 38,920/–रूपए प्रतिमास और अधिकतम उच्चतर वेतन का 50 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(3) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आश्रित परिवार के सदस्य (पति या पत्नी से भिन्न) की आय सीमा, प्रतिमास 30,000/– रूपए (केवल तीस हजार) से कम होनी चाहिए।

परिवारिक पेंशन ।

13. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, ''पारिवारिक पेंशन'' से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (10) के उप–खण्ड (ख) में यथा परिभाषित पारिवारिक पेंशन।

पेंशन का संराशिकरण।

14. संराशिकरण मूल्य, सीमा, जिस तक पेंशन संराशित की जा सकती है अथवा अवधि, जिसके बाद संराशित पेंशन बहाल की जानी है, से संबंधित उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

महँगाई राहत की स्वीकार्यता।

15. इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्रथम जनवरी, 2016 से ''मूल पेंशन'' या ''मूल पारिवारिक पेंशन'' जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा। उसके बाद, प्रथम जनवरी, 2016 से मंहगाई राहत सहित प्राप्त की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, स्वीकृत महँगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्हक होगी।

16. न्यायिक अधिकारियों, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं/या उनकी मृत्यु हुई है और उनके पात्र परिवारिक सदस्यों को वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 2/14/2018-1Pension (FD), दिनांक 12 जून, 2019 के अनुसार मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 30 प्रतिशत की दर पर पहले ही भुगतान की जा चुकी अंतरिम राहत के समायोजन के बाद, पेंशन संवितरण प्राधिकारी प्रथम जनवरी, 2016 से भुगतानयोग्य पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की गणना करेगा और बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का भुगतान।

17. (1) यह सम्भाव्य है कि कुछ मामलों में देय बकायों का अधिक भुगतान गलती से संगणित किया जा सकता है, जो कार्यान्वयन के बाद भी बाद में वसूल किया जाना है। इसलिए पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को बकायों को आहरण करते समय हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों से यह स्पष्ट करवा लेना चाहिए कि यदि बाद में कोई विसंगति ध्यान में आती है, तो भुगतान, उन राशियों से समायोजन के अध्यधीन किया जा रहा है, जो उनको देय होगी। इस प्रयोजन के लिए, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के समय पर प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों से लिखित में इस आशय की वचनबद्धता भी प्राप्त की जाएगी कि अधिक भुगतान, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत समेकन के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है, तो, उस द्वारा सरकार को या तो भविष्य में भुगतान के समायोजन द्वारा या अन्यथा से उक्त राशि वापस की जाएगी। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'क' में दिया गया है। पेंशन/ पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनबद्धता।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेशन का नियतन तथा बकायों का समायोजन भी उन कतिपय मामलों में परिशोधन तथा समायोजन के अध्यधीन होगा, जहाँ विशेष पेंशन या अनन्तिम पेंशन विधि न्यायालय के कुछ अंतरिम आदेशों की सामर्थ्य में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को प्रदान की गई थी, मामले के अंतिम रुप से निर्णित होने के बाद, विधि न्यायालय की टिप्पणी/निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, पेंशन संवितरण प्राधिकारी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का वितरण करते समय हरियाणा सरकार के ऐसे सभी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को यह भी स्पष्ट करेंगे कि विधि न्यायालय के ऐसे अन्तिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए समुचित निर्णय के अध्यधीन भुगतान किए जा रहे हैं। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।

18. इन नियमों या इन नियमों की निरन्तरता में जारी किए गए किन्हीं अन्य पश्चात्वर्ती अनुदेशों में यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा सिविल सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या जारी किए गए अनुदेशों के उपबन्ध, ऐसे मामलों, जहाँ पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक वे इन नियमों से असंगत हों। पंजाब सिविल सेवा नियम वाल्यूम II तथा अन्य नियमों, जो इन नियमों द्वारा विशेष रूप से उपांतरित नहीं किए गए हैं, के उपबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे। अध्यारोही प्रभाव।

19. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो अन्तिम निर्णय के लिए इसे वित्त विभाग में हरियाणा सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा। निर्वचन।

20. किसी समान्य या विशेष परिस्थितियों की स्थिति में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं या जिनके बारे में कतिपय असंगति ध्यान में आई हों, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुपालित की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी। आगे, यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकती है और हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी। अवशिष्ट उपबन्ध।

21. जहाँ सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधो के प्रर्वतन में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो यह आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों, के अध्यधीन इन नियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकती है या में ढील दे सकती है, जो यह मामले को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति में निपटाने के लिए आव यक समझे। ढील देने की शक्ति।

22. पेंशन संवितरण प्राधिकारी/खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लाभ के लिए इन नियमों को अपने सूचनापट्ट पर तत्काल प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शन।

अनुलग्नक क

[देखिए नियम 17(1)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि यदि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत नियतन के परिणामस्वरुप अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है या बाद में ध्यान में आई विसंगतियों के दृष्टिगत कोई अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है, तो मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर..

नाम..

पता...

अनुलग्नक ख

[देखिए नियम 17(2)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि किसी विधि न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के आधार पर मुझे दी गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन में किसी परिशोधन या समायोजन के परिणामस्वरूप कोई अधिक राशि, जो विधि न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए सूसंगत समूचित निर्णय के परिणामस्वरूप का भुगतान किया गया पाया जाता है, तो वह मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा। मैं, आगे ऐसे विधि न्यायालय के यथास्थिति अंतिम निर्णय पर लिए गए सरकार के ऐसे सुसंगत समुचित निर्णय का पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर..

नाम..

पता..

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 5th August, 2024

No. 2/14/2018-1Pension(FD).— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service (Revised Pension) Part - II Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

Applicability of these rules.

2. (1) They shall apply to all Judicial Officers of the Haryana Government, who retire/ die in harness on or after the 1st January, 2016 and who become eligible for pension /family pension under the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016), whose pension /family pension is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

(2) These rules shall not apply to Judges of the Punjab and Haryana High Court.

Date of effect.

3. The revised provision as per these rules shall apply to Judicial Officers, who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016:

Provided that where pension/family pension or death-cum-retirement gratuity/ commutation of pension, has already been sanctioned in cases occurring on or after the 1st January, 2016, the same be revised as per provision of these rules:

Provided further that in cases where pension has been finally sanctioned on pre revised emoluments and if the same happens to be more beneficial than the entitled pension under these rules, the pension already sanctioned shall not be revised to the disadvantage of the pensioner in view of proviso to rule 78 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Emoluments for pension / family pension.

4. The term "emoluments" for the purposes of calculating various pensionary benefits other than death cum retirement gratuity shall mean pay as defined in clause (b) of sub-rule (7) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Basic pay.

5. Basic pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the Pay Matrix with effect from the 1st January, 2016 but does not include any type of pay like special pay etc.

Emoluments for death-cum-retirement gratuity.

6. In the case of all kinds of gratuity, dearness allowance admissible on the date of retirement/death shall continue to be treated as emoluments along with the emolument as defined in terms of rule 4 of these rules.

Pension.

7. A Judicial Officer retiring in accordance with the Punjab Civil Services Rules Vol. II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016) before completing qualifying service of ten years shall not be entitled to pension but he shall continue to be entitled to service gratuity in terms of rules 32 and 35 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Provision for calculation of pension.

8. (1) A Judicial Officer, who retires after rendering the minimum qualifying service of 20 years, shall become entitled to full pension under the provisions of rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

(2) In all such cases, where Judicial Officer becomes entitled to pension on superannuation after completion of 10 years of qualifying service in accordance with the rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, pension shall be calculated on proportion basis to the amount of full pension admissible to him.

Minimum and maximum ceiling of pension and family pension.

9. (1) The amount of pension and family pension shall be subject to a minimum of Rs. 38920/- per month and Rs. 23350/- per month respectively and the maximum Rs. 1,12,050/- per month i.e. 50% (fifty percent) and family pension Rs. 67,230/-per month i.e. 30% (thirty percent) of the highest pay of Rs. 2,24,100/-per month in the Government of Haryana with effect from the 1st January, 2016.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply in those cases where the length of service of a Judicial Officer at the time of his retirement is less than 20 years. The pension of these Judicial Officers shall be calculated proportionately as per provisions specified in the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 keeping in view his length of service.

Additional pension/family pension.

10. (1) The quantum of additional pension/family pension available to the retired *Judicial Officers and their eligible family members* shall be as mentioned in the table given below, namely:-

Table

Serial Number	Attaining age of pensioner /family pensioner	Additional quantum of pension/family pension
1	2	3
1	From 75 years to less than 80 years	20% of revised basic pension/family pension
2	From 80 years to less than 85 years	30% of revised basic pension/family pension
3	From 85 years to less than 90 years	40% of revised basic pension/family pension
4	From 90 years to less than 95 years	60%of revised basic pension/family pension
5	From 95 years to less than 100 years	80%of revised basic pension/family pension
6	100 years or more	100 % of revised basic pension/family pension

(2) The Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana shall ensure that the date of birth and the age of the pensioners/family pensioners is invariably indicated in PEN-I and the Pension Payment Order (PPO) to facilitate payment of additional pension/ family pension by Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. If the requisite information is not available in the PEN-1(issued by the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana) in those cases, the requisite information may be obtained from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana before adding the additional pension/family pension in the existing basic pension / family pension. The amount of additional pension family pension shall be shown distinctly in the pension/family pension payment order.

Illustration: In case where a pensioner/family pensioner is more than 75 years of age and his/her consolidated pension/family pension in terms of rule 8 of these Rules is, Rs. 10,000/-per month, the pension/family pension shall be shown as (i) basic pension/ family pension Rs. 10,000/-and (ii) additional pension/ family pension Rs. 2,000/- per month.

(3) The additional quantum of pension/family pension on attaining the age of 75 years and above shall be admissible from the first day of the month in which his date of birth falls.

Illustration: If a pensioner / family pensioner completes age of 75 years on any date in the month of May, 2023, he shall be entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st May, 2023.

(4) Dearness relief shall also be admissible on the additional quantum of pension/family pension available in accordance with the orders issued from time to time.

Death-cum-retirement gratuity.

11. (1) The maximum limit of death-cum-retirement gratuity shall be Rs. 20.00 Lakh (Rs. Twenty Lakh). The ceiling on gratuity shall increase by 25% (twenty five percent) whenever the dearness allowance rises by 50% (fifty percent) of the basic pay.

(2) The rate of death gratuity is revised as under:-

Table

Serial number	Length of qualifying service upto the date of death	Rate of death gratuity
1	**2**	**3**
1	Less than 1 year	2 times of monthly emoluments
2	1 year or more but less than 5 years	6 times of monthly emoluments.
3	5 year or more but less than 11 years	12 times of monthly emoluments.
4	11 year or more but less than 20 years	20 times of monthly emoluments.
5	20 years or more	half month of emolument for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emolument.

Family Pension Scheme, 1964.

12. (1) Family Pension shall be calculated at a uniform rate of 30% (thirty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs. 23,350/- per month and maximum of Rs. 67,230/- per month *i.e.* 30% (thirty percent) of the highest pay of Rs. 2,24,100/- in Government of Haryana with effect from the 1st January, 2016.

(2) The amount of enhanced family pension shall be 50% (fifty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs. 38,920/- per month and maximum of 50% of the highest pay in the Government of Haryana.

(3) Income limit of dependent family member (other than spouse) to get family pension should be less than Rs. 30,000/- (Thirty Thousand only) per month.

Family pension.

13. For the purpose of these rules, "family pension" means, the family pension as defined in sub-clause (b) of clause (10) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Commutation of pension.

14. There shall be no change in the provisions relating to commutation values, the limit upto which the pension may be commuted or the period after which the commuted pension is to be restored.

Admissibility of dearness relief.

15. The consolidated pension / family pension as worked out in accordance with the provisions of these rules shall be treated as "Basic Pension" or "Basic Family Pension", as the case may be, with effect from the 1st January, 2016. The revised pension/family pension arrived includes dearness relief from the 1st January, 2016 and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter.

Payment of arrears of pension/family pension.

16. The Pension Disbursing Authorities shall calculate the arrears of revised pension / family pension payable with effect from the 1st January, 2016 after adjustment of interim relief already paid @ 30% of the basic pension /family pension to the Judicial officers, who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016 and their eligible family members vide Finance Department UO No. 2/14/2018-1Pension (FD), dated the 12th June, 2019 and the balance amount shall be paid immediately.

Undertaking for recovery of over payment of Pension /Family pension and gratuity.

17. (1) It is not unlikely that the arrears due in some cases may be calculated incorrectly leading to over payment that might have to be recovered subsequently. The Pension Disbursing Authorities shall, therefore, make it clear to the retired Judicial Officers and their eligible family members while drawing arrears of pension that the payments are being made subject to adjustments from amounts that may be due to them, if any, discrepancy is noticed later. For this purpose, an undertaking shall be obtained in writing from every retired Judicial Officer and his eligible family member at the time of revision of pension/family pension to the effect that excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect consolidation of pension /calculation of arrears shall be refunded by him to the Government either by adjustment against future payment or otherwise. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure A.

(2) The fixation of pension / family pension and adjustment of arrears shall also be subject to rectification and adjustments in certain cases where a particular pre-revised scale or provisional pension has been granted to retired Judicial Officers and their eligible family members at the strength of some interim orders of the court of law, after the final disposal of the case suitable appropriate decision may be taken by the Government keeping in view the observations / instructions of the Court of Law. The Pension Disbursing Authority shall, therefore, also make it clear to all such concerned retired Judicial Officers and their eligible family members while disbursing the arrears/ pension that payments are being made subject to appropriate decision taken by the Government on such final decision of the court of law. A specimen form of undertaking is also enclosed as Annexure B.

Overriding effect.

18. The provisions of the Haryana Civil Services Rules or the Punjab Financial Rules or any other rules or instructions made or issued in this regard shall not, save as otherwise provided in these rules or any other subsequent instructions issued in continuation to these rules, apply to cases where pension/ family pension and death-cum-retirement gratuity is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with the provisions of these rules. The provisions of the Punjab Civil Services Rules Volume II and other rules which are not specifically modified by these rules shall remain unchanged.

19. If any question arises relating to the interpretation of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government of Haryana in Finance Department for final decision. Interpretation.

20. In the event of any general or special circumstance which is not covered under these rules or about which certain inconsistencies are noticed, the matter shall be referred to the Government and the Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions, the Government may prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government of Haryana, Finance Department under this rule, shall be deemed to be the part of these rules. Residuary provisions.

21. Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Power to relax.

22. The Pension Disbursing Authorities/ Treasury Officers / Assistant Treasury Officers shall promptly display these rules on their notice board for the benefit of retired judicial officers. Display.

ANNEXURE A

[see rule 17 (1)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that in case excess payment is found to have been made as a result of incorrect fixation of pension/family pension or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature ——————————

Date: Name ——————————

Place: Address ——————————

ANNEXURE B

[see rule 17 (2)]

UNDERTAKING

I hereby undertake that as a result of any rectification or adjustment in the pension/family pension granted to me on the basis of any interim order by any court of law, any excess amount which is found to have been made as a result of relevant appropriate decision taken by the Government on the final decision of the court of law, shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise. I further undertake to abide by such relevant appropriate decision of the Government taken on the final decision of such court of law as the case may be.

Signature————————

Date: Name ————————

Place: Address————————

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

11222—C.S.—H.G.P., Pkl.